दुष्यंत साफ-साफ बताओ, क्या तुम भाजपा से समझौता करोगे

हरियाणा की जाट बेल्ट हिंदूवादी पार्टी को उखाड़ने के लिए तैयार बशर्ते....

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

रोहतक: हरियाणा में चौटाला खानदान की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं लेकिन उसी के साथ इस परिवार के भाजपा के साथ संबंधों को लेकर संशय के बादल छट नहीं रहे हैं। यह संशय तब भी बना हुआ है जब अजय चौटाला के बेटों ने अपने दम पर जननायक जनता पार्टी खड़ी कर दी है और दूसरी तरफ अभय चौटाला हरियाणा में अपनी जन अधिकार यात्रा के अगले चरण की घोषणा कर चुके हैं। अभय चौटाला ग्रुप की ओर से और दूसरी तरफ दुष्यंत और दिग्विजय की तरफ से इस संशय को मिटाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ऐसे में हरियाणा की जाट बेल्ट में इनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थितियां अनुकूल लेकिन नेता बावले हैं

अभय और दुष्यंत की राजनीति पर बात करने से पहले हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक सीन की चर्चा जरूरी है। कुछ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से और कुछ हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लचर प्रशासन की ओर से हरियाणा में भाजपा की अपनी स्थिति गर्त में जा रही है। तीन हिंदी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के बाद हरियाणा की चौपालों पर भाजपा और खट्टर से छुटकारा पाने के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो चुकी है।

हरियाणा में नाकारा कांग्रेस की चुप्पी और चौटाला खानदान की आपसी लड़ाई के बावजूद लोग राज्य में खट्टर सरकार से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि सरकार बदलने की स्थिति में विकल्प के रूप में सिर्फ .ही चेहरे मौजूद हैं इसके बावजूद लोग दांव लगाने को तैयार बैठे हैं।

हरियाणा में जाट बेल्ट यहां की राजनीति में शुरू से हावी रही है लेकिन तीन दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जाटों के हाथ से राजनीति निकलकर गैर जाटों के हाथों में चली गई। इसका जिम्मेदार हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, जींद और कुरुक्षेत्र आदि के जाट मतदाता भाजपा को मान रहे हैं। हालांकि भाजपा अपने यहां कांग्रेस के चौधरी बीरेंद्र सिंह को तोड़कर ले आई लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको डंप कर दिया। यही नहीं भाजपा में और भी कई जाट नेता हैं लेकिन सभी डंप कर दिए गए हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट बेल्ट के लोगों ने शिद्दत के साथ इस बात को महसूस किया कि भाजपा के जाट नेता उनकी आकांक्षा और उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए जाट बेल्ट के लोग अगले चुनाव की इंतजार में हैं कि वो जल्द से जल्द हरियाणा को भाजपा मुक्त कर दें।

इतनी अनुकूल हालात के बावजूद कांग्रेस और चौटाला खानदान अपनी-अपनी ढपली बजाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वोटर थक हारकर उसे सत्ता सौंप देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नाउम्मीदी चौटाला खानदान से हो रही है। जाट बेल्ट के लोग डरे हुए हैं कि अगर कांग्रेस आपसी गुटबाजी का शिकार हुई और उधर चौटाला खानदान में से कोई एक गुट सशक्त होकर नहीं निकला तो जाट वोटर बिखर जाएंगे और भाजपा उसका पूरा फायदा उठा लेगी।

भाजपा पर अपनी स्थिति साफ करे चौटाला खानदान

दुष्यंत चौटाला ने एक तरफ तो जननायक जनता पार्टी खड़ी कर दी। 9 दिसंबर को जींद में एक बड़ी रैली करके उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। लेकिन जाट बेल्ट में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि दुष्यंत चुनाव के समय भाजपा से चुनावी गठबंधन न कर लें। दुष्यंत की ओर से अभी तक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस बीच उनकी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की खबरें भी आईं। इसके बावजूद दुष्यंत ने यह नहीं बताया कि आखिर वह मुलाकात किसलिए हुई थी और किसकी तरफ से थी।

दुष्यंत को अगर जाट मतदाताओं का समर्थन हासिल करना है तो उन्हें सबसे पहले यह साफ करना होगा बल्कि टीवी और लिखित रूप से बयान देना होगा कि वे किसी भी सूरत में भाजपा से किसी तरह का राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे। हरियाणा में इस वक्त अगर जाट किसी पार्टी से सबसे ज्यादा नाराज है तो वह भाजपा है। ऐसे में दुष्यंत की ओर से सफाई तो बनती है। आने वाले वक्त में इस बात पर मजदूर मोर्चा की नजर रहेगी कि दुष्यंत भाजपा को लेकर किस हद तक साफ्ट रहते हैं या फिर खुली जंग का ऐलान करते हैं।

दुष्यंत की तरह अभय चौटाला भी भाजपा की आलोचना दबी जुबान से कर रहे हैं। अगर वह प्रमुख विपक्षी दल होने का दम भरते हैं तो उन्हें भाजपा की आलोचना उस सुर में करनी चाहिए जिस सुर में बाकी विपक्षी दल कर रहे हैं। अपनी जन अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने हरियाणा से जुड़े कुछ जमीनी मुद्दे जरूर उठाए लेकिन उसके लिए हरियाणा सरकार से जवाब मांग नहीं सके। अभय की पार्टी इनैलो की ओर से ईमानदारी से एक भी बड़ा आंदोलन प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया।

बीच में हालात ऐसे बन गए थे कि उनकी जन अधिकार यात्रा का अगला चरण शुरू होने पर संशय था लेकिन शुक्रवार को उसका ऐलान कर दिया गया। तीसरे चरण में यात्रा 20 हल्कों से होकर गुजरेगी, जिसमें 17 दिसंबर को ऐलनाबाद और सिरसा, 18 को तोशाम व बाढड़ा, 20 तारीख को बरोदा-सफीदों, 21 को होडल-पुन्हाना और 22 दिसंबर को यह यात्रा बावल व नारनौल पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा 26 दिसंबर को खरखौदा-बहादुरगढ़, 27 को महेंद्रगढ़-दादरी, 28 को महम-नारनौंद, 29 को बवानी खेड़ा व नलवा और तीसरे चरण के अंत में 30 दिसंबर को यात्रा कलायत और असंध में होगी। बीच में कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली करने की भी योजना है। जन अधिकार यात्रा की इतनी बड़ी कवायद के बावजूद अभय चौटाला का भाजपा विरोधी रुख साफ नहीं हो पा रहा है।

अभय चौटाला के क्रिया कलापों को लेकर जाट बेल्ट में यह चर्चा आम है कि चुनाव के नजदीक अपना मकसद पूरा करने के लिए अभय चौटाला भाजपा से चुनावी समझौता कर सकते हैं। भाजपा नेतृत्व के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि नाराज जाट या तो सारा का सारा अभय के साथ जाएगा या फिर दुष्यंत का दामन थाम सकता है। अगर कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से कमान सौंपता है तो भी कांग्रेस को जाट बेल्ट में समर्थन मिल सकता है। क्योंकि जाट बेल्ट अब अपने नेताओं की वापसी चाहती है ताकि वक्त आने पर जाट लॉबी को संरक्षण मिल सके।

राजस्थान के संकेत को समझे हरियाणा

राजस्थान के कम से कम पांच जिले ऐसे हैं, जहां जाट मतदाताओं ने कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में इस बार अच्छे खासे जाट विधायक चुन कर पहुंचे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस के हैं। हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं, जिनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। झुंझनू, अलवर आदि कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां के जाटों की रिश्तेदारियां हरियाणा के सिरसा, झज्जर, भिवानी आदि में हैं। वहां के जाटों ने कांग्रेस को वोट देकर साफ संकेत दिया है कि भाजपा को भगाने के लिए वो किसी भी ठोस विकल्प की तरफ मुड़ सकते हैं। अगर हरियाणा में जाट बेल्ट को लगा कि कांग्रेस के अलावा भी उसके पास अभय या दुष्यंत के रूप में सशक्त विकल्प है तो वह इन्हें भी आजमाने में कसर नहीं छोड़ेगा।

कांग्रेस को भी फायदा

दुष्यंत और अभय चौटाला की ओर से भाजपा का लेकर स्थिति साफ न करने की वजह से जाट बेल्ट कांग्रेस की तरफ मुड़ सकती है लेकिन कांग्रेस को अपनी जाट लीडरशिप का चेहरा साफ करना होगा। अभी जिस तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस ने पुराने नेताओं पर ही दांव खेला है तो ऐसे में अगर वह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर लाती है तो उसे फायदा ज्यादा होगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस नेतृत्व की ओर से अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। लेकिन यह साफ है कि हरियाणा में जाटों को अपने खेमे में लाये बिना कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी नहीं कर सकती।

मंझावली पुल का देकर झांसा यमुना पार जाने वालों को फ़ांसा

फ़रीदाबाद (म.मो.) 15 अगस्त 2014 को स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने यमुना के मंझावली घाट पर लाखों की भीड़ एकत्र करके वहां चार मार्गी पुल बनाने का ड्रामा किया था। जनता को इस ड्रामे पर भरोसा कराने के लिये बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी को बुलाया गया था। उस वक्त घोषणावीर मंत्रियों द्वारा दो साल में पुल चालू करने की घोषणा की गयी थी। करीब चार साल बीतने के बाद कृष्णपाल ने 31 दिसम्बर तक इसे चालू करने की घोषणा की।

घोषणावीरों की इन घोषणाओं के चक्कर में मंझावली घाट पर नाव चलाने के ठेका भी नहीं दिया गया। विदित है कि नदी के उस पार दैनिक आने-जाने वाले हजारों लोग़ों का एक मात्र सहारा नाव ही थी जिसे मंत्री गूजर ने बंद करवा दिया। ऐसे में मजबूरन जनता लोहे के उस अस्थाई पुल का इस्तेमाल कर रही है जिसे पुल निर्माता कम्पनी ने निर्माण सामग्री एवं अन्य आवश्यक साजो-सामान लाने ले जाने के लिये बनाया है। आने- जाने वाले लोग पैदल ही नहीं होते बल्कि उनके दुपहिया वाहन व पशु आदि भी होते हैं। पुल के अस्थाई होने के चलते इसे राहगीरों के लिये सुरक्षित भी नहीं बनाया गया है।

जाहिर है यहां अस्थाई पुल राहगीरों के लिये असुरक्षित है वहीं पुल निर्माता कम्पनी के लिये निर्माण कार्य करना दूभर हो रहा है क्योंकि अस्थाई पुल की क्षमता इतनी नहीं है कि निर्माण सामग्री लाने-ले जाने के साथ-साथ जनता का भी आवागमन होता रहे। ऐसे में निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इसके चलते निर्माण कार्य लगभग थम सा गया है। इसलिये निर्माण कम्पनी ने पीडब्लूडी के माध्यम से पुलिस व उपायुक्त को शिकायत कर लोग़ों के आवागमन को रोकने की मांग की है।

ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यदि ज़िला प्रशासन ने बल प्रयोग द्वारा जनता का आवागमन थाम दिया तो लोग नदी पार कैसे आवागमन करेंगे? हां, यदि सरकार की नीयत साफ़ एवं जनविरोधी नहीं है तो तुरंत बिना किसी टेंडर या ठेके के नाव चलाने की अनुमति दी जाय।

संदर्भवश सुधी पाठक यह भी जान लें कि चार मार्गी यमुना पुल के चालू होने के आसार अभी, कम से कम एक वर्ष तक तो नहीं हैं। दूसरे पुल तक पहुंचने के लिये आवश्यक 4 मार्गी सड़क निर्माण का काम तो अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। ऐसे में 5 गांवों की संकरी गलियों से इतना भारी भरकम यातायात कैसे गुजर पायेगा?

ताजातरीन जानकारी के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त गांवों की गलियों को चौड़ा करने की अपेक्षा इन गांवों के बाहर से बाइपास बनाये जायें। इसके किसानों से मोल-भाव करके ज़मीनों के रेट तय करने के बाद भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव सरकारी मंजूरी हेतु चंडीगढ भेजा जा रहा है। है न मजेदार बात! पूरे 4 साल बाद अभी तो सरकार को यह समझ आया है कि यहां से भारी-भरकम यातायात को गुजारने के लिये चौड़े बाईपास बनाने की जरूरत है। अब देखना यह है कि कब तो चंडीगढ से मंजूरी आयेगी, कब भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा और कब बाइपास बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि बीते चार बरसों में हर दूसरे-तीसरे माह मंत्री गूजर महोदय इसी पुल का राग अलाप अलाप कर प्रेस नोट जारी करते रहे हैं। कई बार अखबारों में छपवा चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिये कमेटी बनाई गयी है, किसानों की अधिग्रहीत होने वाली भूमि के रेट तय हो चुके हैं और यहां तक कि भूमि अधिग्रहण होने वाला है। परन्तु वास्तव में हुआ कुछ भी नहीं है।

आगामी चार माह बाद जनता गूजर महोदय व इनकी जुमलेबाज सरकार को बाहर का रास्ता दिखा देगी तो यह कार्य आने वाली कोई और ही सरकार पूरा करेगी।

सेक्टर 25 को जोड़ने वाला टूटा पुल

सोहना रोड को औद्योगिक सेक्टर 25 से जोड़ने वाली सड़क पर गुड़गांव नहर पार करने हेतु बना पुल टूटे करीब 6 माह हो चुके हैं। इसकी वजह से जनता किस कदर परेशान है, कितना लम्बा चक्कर काट कर उन्हें अपना समय व पैट्रोल बर्बाद करना पड़ता है, इसकी कोई चिंता घोषणावीरों की इस सरकार को नहीं है।

सरकारी फ़ाइलों में दबा इसका निर्माण कार्य यदि फ़ाइलों से बाहर निकल आये तो पुल के निर्माण में एक माह से अधिक का कोई काम नहीं है। लेकिन फ़ाइलों से बाहर निकालने की सरकार को जल्दी क्या है? जनता भुगत रही है तो भुगते, जनता होती ही भुगतने के लिये है।

मुख्य डाकघर के सामने टूटी पुलिया

एनआईटी के नेहरू ग्राऊंड स्थित शहर के मुख्य डाकघर के सामने नाले पर बनी एक छोटी सी पुलिया गत लगभग 3 माह से टूटी पड़ी है। यदि नगर निगम की नीयत साफ़ हो तो इसके पुनर्निमाण का काम किसी भी तरह दो दिन से अधिक का नहीं है। लेकिन जनहित का काम तो इन्होंने करना ही नहीं, सभी अधिकारी इसी गुणा-भाग में लगे रहते हैं कि उन्हें इस कार्य से क्या लाभ होने वाला है।

विदित है कि नेहरू ग्राऊंड शहर का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। इसमें प्रतिदिन हज़ारों वाहनों का आवागमन होता है। इस पुलिया के टूट जाने से क्षेत्र में प्रवेश के अन्य मार्गों पर सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है।